पूरी बेंच

न्यायमूर्ति एस.एस. संधावालिया सी.जे., एस.सी. मितल और सी.एस. तिवाना के समक्ष

कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय और अन्य,-अपीलकर्ता

बनाम

ग्रामीण शिक्षा महाविद्यालय, कैथल, प्रतिवादी

1978 का पत्र पेटेंट अपील संख्या 630

22 नवंबर, 1979

कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय अधिनियम (1956 का बारहवीं)-धारा 15 और अध्यादेश 1, खंड (2)-विश्वविद्यालय आर.एड में प्रवेश के लिए कॉलेजों को गाइड-लाइन जारी करता है। पाठ्यक्रम-हरियाणा अधिवास के अभ्यर्थियों को ही प्रवेश देने का निर्देश दिया गया है। दिशानिर्देशों की वैधता को चुनौती दी गई है। ऐसे दिशानिर्देशों को चुनौती दी गई है-क्या उनके पास कोई वैधानिक स्रोत है-क्या उनका उल्लंघन किया गया है। क्या यह कॉलेजों की असंबद्धता का आधार है।

माना गया कि अन्य बातों के अलावा दिशानिर्देश सीटों के आरक्षण, उम्मीदवारों की पात्रता के लिए प्रदान करते हैं और इसमें विशिष्ट प्रावधान शामिल है कि बीएड में प्रवेश के लिए हरियाणा अधिवास अनिवार्य होगा। अवधि। दिशानिर्देश वेटेज, पात्रता और योग्यता सूची के साथ-साथ शिक्षा के मान्यता प्राप्त कॉलेजों के लिए प्रवेश प्रक्रिया आदि के लिए भी प्रदान करते हैं। दिशानिर्देशों की सामग्री और अध्यादेश के प्रावधानों को देखते हुए मैंने कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत तैयार किया है। 1956, ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि जारी किए गए दिशानिर्देश अध्यादेश 1 के खंड (2) द्वारा चित्रित क्षेत्र के भीतर निष्पक्ष और स्पष्ट रूप से आते हैं। अध्यादेश 1 का खंड (1), हालांकि, एक प्रवेश समिति के गठन का प्रावधान करता है और इसके उप-खंड (ए) से (एफ) उन कर्मियों को निर्धारित करते हैं जिन्हें विभिन्न स्तरों पर और विभिन्न संस्थानों में इन प्रवेश समितियों का गठन करना है। उप-खंड (सी) (iii) शिक्षा महाविद्यालयों सहित व्यावसायिक महाविद्यालयों से संबंधित है जो विशेष रूप से और स्पष्ट रूप से इस अध्यादेश के दायरे में आते हैं। अध्यादेश 1 का खंड (2) प्रवेश समिति को यह तय करने का अधिकार देता है कि विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त या संचालित कॉलेजों में प्रवेश किस प्रकार विनियमित किया जाएगा। यह शक्ति, जिसे व्यापक रूप से वर्णित किया गया है, इतनी स्पष्ट है कि किसी भी विस्तार की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, यदि कोई आवश्यकता थी तो उसे उप-खंड (ii) (ए) (बी) (सी) और (डी) द्वारा प्रदान किया जाता है। ये, शर्तों में, प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की योग्यता

सूची तैयार करने, उपलब्ध सीटों की संख्या, तिथियों की अनुसूची और सभी प्रकार के अवशिष्ट प्रश्नों को तैयार करने के सिद्धांत प्रदान करते हैं जिन्हें प्रवेश समिति को भेजा जा सकता है। कुलपति द्वारा प्रदान किया जा सकता है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि दिशानिर्देश अधिनियम के प्रावधानों के तहत बनाए गए अध्यादेश 1 द्वारा प्रदान की गई वैधानिक मंजूरी के भीतर पूरी तरह से शामिल हैं और इसलिए वैध हैं। नतीजतन, इसका मतलब यह होगा कि दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए, विश्वविद्यालय कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई करने और संबद्धता वापस लेने और इसके उल्लंघन में प्रवेश पाने वाले छात्रों को पंजीकरण से इनकार करने का हकदार था।

(पैरा 7, 8, 9, 10 और 12)

9 अक्टूबर, 1978 को सी.डब्ल्यू.पी. में माननीय श्री न्यायमूर्ति गुरनाम सिंह द्वारा पारित आदेश के खिलाफ लेटर्स पेटेंट के खंड एक्स के तहत अपील 1978 का क्रमांक 1357 |

एस. सी. मोहन्ता, वकील, विश्वविद्यालय के लिए।

नौबत सिंह, वरिष्ठ डी.ए.जी., हरियाणा राज्य के लिए।

प्रतिवादी की ओर से कुलदीप सिंह, अधिवक्ता, आर.एस. मोंगिया, अधिवक्ता के साथ

निर्णय

न्यायमूर्ति एसएस संधावाला, सीजे

1. क्या कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा बी.एड में प्रवेश के प्रयोजनों के लिए संबद्ध सभी शिक्षा महाविद्यालयों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं? 1977-78 के सत्र के लिए पाठ्यक्रम (अनुलग्नक पी. 3), कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय अधिनियम, 1956 के तहत बनाए गए अध्यादेश 1 के वैधानिक प्रावधानों के दायरे में हैं, एकान्त हैं; यद्यपि सार्थक, प्रश्न जो लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के तहत इस अपील में उठता है।

2. यद्यपि उपरोक्त मुद्दा स्पष्ट रूप से कानूनी है, फिर भी इसे जन्म देने वाले तथ्यों के मैट्रिक्स में कुछ विस्तृत नोटिस की आवश्यकता है। रूरल कॉलेज सोसायटी द्वारा प्रबंधित रूरल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, कैथल, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत एक निकाय है । इसकी स्थापना वर्ष 1970 में हुई थी और इसमें कोई गंभीर विवाद नहीं है कि सोसायटी का एक उद्देश्य और उद्देश्य ग्रामीण जनता के बीच सामाजिक और राजनीतिक शिक्षा के लिए शैक्षणिक संस्थानों को बनाए रखना था। मूल रूप से, यह संस्थान पंजाब विश्वविद्यालय से संबद्ध था, जिसका उस

समय इस क्षेत्र पर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र था, लेकिन जुलाई 1978 में इसे वहां से असंबद्ध कर दिया गया और कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय से संबद्ध कर दिया गया। प्रतिवादी कॉलेज और विश्वविद्यालय के बीच मुकदमेबाजी का एक इतिहास है जिसकी अब कोई प्रासंगिकता नहीं है और यह उल्लेख करना पर्याप्त है कि 1977-78 के सत्र के लिए, विश्वविद्यालय ने बी.एड में प्रवेश के लिए दिशानिर्देश आगे बढ़ाए थे। कक्षाएं (रिट याचिका के लिए अनुलग्नक पी/3) और आगे निर्देश दिया कि हरियाणा में अधिवास रखने वाले छात्र, चाहे वे ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों से संबंधित हों, प्रवेश के लिए पात्र होंगे। प्रतिवादी-कॉलेज ने दिशानिर्देश जारी करने पर आपत्ति जताते हुए आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय के पास छात्रों को प्रवेश देने के अपने अधिकार को रोकने का कोई अधिकार नहीं है और न ही उसे निर्देशों के तहत केवल हरियाणा राज्य के छात्रों तक ही प्रवेश सीमित करने के लिए मजबूर किया जा सकता है, भले ही वे शहरी या ग्रामीण हों। पृष्ठभूमि।

3. कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के बावजूद, प्रतिवादी-कॉलेज ने 24 जुलाई, 1977 के 'द ट्रिब्यून' में एक प्रवेश सूचना डाली कि केवल भारत में कहीं भी किसी गाँव में जन्मे या शिक्षित व्यक्तियों को ही कॉलेज में प्रवेश के लिए आवेदन करने की आवश्यकता है। छात्रों के प्रवेश के चरण में, विश्वविद्यालय ने डॉ. एपी शर्मा और डॉ. बीआर गुप्ता को प्रतिवादी कॉलेज की रिपोर्ट करने वाले अन्य लोगों के साथ अध्यादेश-1 के तहत गठित प्रवेश समिति का सदस्य नियुक्त किया। कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय (जिसे इसके बाद विश्वविद्यालय कहा जाएगा) का प्रतिनिधित्व करने वाले उपरोक्त दो सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया कि हरियाणा में अधिवास रखने वाले छात्रों को इस तथ्य की परवाह किए बिना कि वे ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों से हैं, उन्हें प्रवेश दिया जाना चाहिए और जब अन्य लोग इस पर सहमत नहीं हुए, तो दोनों नामांकित सदस्य विरोध के कारण समिति से हट गए और प्रवेश साक्षात्कार में भाग नहीं लिया। शेष सदस्यों ने 100 छात्रों को प्रवेश दिया, जिन्होंने भारत में कहीं भी ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। हालांकि, विश्वविद्यालय ने यह रुख अपनाया कि यह प्रवेश जारी किए गए दिशानिर्देशों का अपमान है। इसके परिणामस्वरूप यह अंततः अवैध हो गया, लेकिन प्रतिवादी-कॉलेज के शासी निकाय के अध्यक्ष अपने रुख पर अड़े रहे और दिशानिर्देश जारी करने की विश्वविद्यालय की शक्ति पर सवाल उठाया। अंततः, अपीलकर्ता-विश्वविद्यालय ने एक कारण बताओ नोटिस जारी किया कि क्यों न उसे असंबद्ध कर दिया जाए क्योंकि उन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पेटेंट उल्लंघन करते हुए छात्रों को प्रवेश दिया था, जिस पर प्रतिवादी-कॉलेज ने यह रुख अपनाया कि विश्वविद्यालय के पास जारी करने की कोई शक्ति नहीं है। दिशानिर्देश. अंततः, विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने रिट याचिका के अपने पत्र अनुलग्नक पी/12 के माध्यम से कॉलेज को 1977-78 के सत्र से असंबद्ध करने का निर्णय लिया और आगे सूचित किया कि कॉलेज द्वारा प्रवेशित छात्र विश्वविद्यालय द्वारा पंजीकृत नहीं हैं। .

4. दिशा-निर्देशों, अनुलग्नक पी/3 को लागू करने के विश्वविद्यालय के आग्रह और कॉलेज की असंबद्धता से व्यथित होकर, वर्तमान अपील को जन्म देने वाली रिट याचिका को प्राथमिकता दी गई। विद्वान एकल न्यायाधीश, जिनके समक्ष यह मामला पहली बार आया था, ने यह विचार किया कि चूंकि कॉलेज का रखरखाव ग्रामीण क्षेत्रों से एकत्र किए गए धन से किया जा रहा था, इसलिए सोसायटी के पास प्रथम दृष्टया कॉलेज में छात्रों के प्रवेश को विनियमित करने की शक्ति थी, और इस बात से भी संतुष्ट नहीं थे कि विश्वविद्यालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं। विश्वविद्यालय अध्यादेशों को कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत ही तैयार किया गया है, यह मानते हुए कि यह रिकॉर्ड से परे है कि कानून के किन प्रावधानों के तहत दिशानिर्देश, अनुलग्नक पी/3 जारी किए गए थे, इसे अवैध करार दिया गया और इसके परिणामस्वरूप यह भी निर्धारित किया गया। विश्वविद्यालय की असंबद्धता को छोड़कर।

5. यह लेटर्स पेटेंट अपील सबसे पहले डिवीजन बेंच के सामने आई, जिन्होंने अपने संदर्भ आदेश में यह विचार किया था कि एक मान्यता प्राप्त कॉलेज में छात्र के प्रवेश को नियंत्रित करने और विनियमित करने की शक्ति रखने वाले विश्वविद्यालय के बारे में बड़ा प्रश्न एक आधिकारिक निर्णय के योग्य है। एक बड़ी बेंच और इसी तरह मामला हमारे सामने है।

6. अब तर्क वास्तव में एक बहुत ही संकीर्ण दायरे में सिमट गया है: अपीलकर्ता-विश्वविद्यालय के विद्वान वकील श्री एससी मोहंता ने तीखा तर्क दिया है और हमारा विचार सही है कि अब एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या दिशानिर्देश अनुलग्नक पी/3 विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिनियम और उसके तहत जारी अध्यादेश की वैधानिक मंजूरी है? वकील ने इस तर्क पर जोर दिया कि विवादित दिशानिर्देश पूरी तरह से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत बनाए गए अध्यादेश-1 के दायरे में हैं। चूंकि पूरा तर्क अनिवार्य रूप से इसके प्रावधानों के प्रासंगिक हिस्से के इर्द-गिर्द घूमता है, इसलिए शुरुआत में ही अध्यादेश-1 के खंड (2) को पढ़ना आवश्यक है;

"प्रवेश समिति.

(1) xxxx (2) प्रवेश समिति, अध्यादेशों के प्रावधानों के अधीन, निर्णय लेगी:--

(i) वह तरीका जिससे विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों और विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त/संचालित कॉलेजों में प्रवेश को विनियमित किया जाएगा;

(ii) विशेष रूप से और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, समिति निर्धारित कर सकती है:--

(ए) प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की योग्यता सूची तैयार करने के सिद्धांत, और उम्मीदवारों की श्रेणियां जिनके लिए कोई सीटें आरक्षित की जानी हैं और/या जिन्हें योग्यता सूची में प्लेसमेंट के लिए कोई वेटेज की अनुमति दी जानी है;

(बी) विभागों और कॉलेजों में उपलब्ध होने वाली सीटों की संख्या;

(सी) विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए तारीखों की अनुसूची;

(डी) ऐसे अन्य मामले जिन्हें कुलपति द्वारा संदर्भित किया जा सकता है। उपरोक्त के आलोक में, मामले का मूल यह है कि क्या उपरोक्त प्रावधान दिशानिर्देशों के लिए पर्याप्त वैधानिक स्रोत हैं, अनुबंध पी/3।

7. अब अनुलग्नक पी/3 का संदर्भ यह संकेत देगा कि यह स्पष्ट रूप से है। बी.एड में प्रवेश के लिए सभी शिक्षा महाविद्यालयों को एक दिशानिर्देश का सख्ती से पालन करना होगा। अवधि। अन्य बातों के अलावा यह सीटों के आरक्षण, उम्मीदवारों की पात्रता और इसमें शामिल विशिष्ट प्रावधान है जो विवाद का कारण है, अर्थात्, बीएड में प्रवेश के लिए हरियाणा अधिवास अनिवार्य होगा। अवधि। दिशानिर्देश वेटेज, पात्रता और योग्यता सूची के लिए भी प्रदान करते हैं। शिक्षा के मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया आदि।

8. अब अनुबंध पी/3 की सामग्री और अध्यादेश-1 के प्रावधानों को देखते हुए, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि जारी किए गए दिशानिर्देश खंड (2) द्वारा चित्रित क्षेत्र के भीतर निष्पक्ष और स्पष्ट रूप से आते हैं। अध्यादेश-1. हालाँकि, यह सबसे पहले ध्यान देने योग्य है कि अध्यादेश -1, खंड (1), एक प्रवेश समिति के गठन का प्रावधान करता है और उसके उप-खंड (ए) से (एफ) उन कर्मियों को निर्धारित करते हैं जो विभिन्न स्थानों पर इन प्रवेश समितियों का गठन करते हैं। स्तरों और विभिन्न संस्थानों में। उप-खंड (सी) (iii) शिक्षा महाविद्यालयों सहित व्यावसायिक महाविद्यालयों से संबंधित है जो विशेष रूप से और स्पष्ट रूप से इस अध्यादेश के दायरे में आते हैं।

9. अब अध्यादेश-1 का खंड (2) प्रवेश समिति को यह तय करने का अधिकार देता है कि विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त या संचालित कॉलेजों में प्रवेश किस प्रकार विनियमित किया जाएगा। यह शक्ति जिसे व्यापक रूप से शब्दबद्ध किया गया है, किसी भी विस्तार की आवश्यकता के लिए बहुत सरल है: हालाँकि, यदि कोई आवश्यकता थी, तो उसे उप-खंड (ii) (ए) (बी) (सी) और (डी) द्वारा प्रदान किया गया है। इन; शर्तों में यह प्रावधान है कि प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की मेरिट सूची तैयार करने के सिद्धांत, की संख्या। उपलब्ध सीटें, तारीखों की अनुसूची और सभी प्रकार के अवशिष्ट प्रश्न जो कुलपति द्वारा प्रवेश-समिति को भेजे

जा सकते हैं, प्रदान किए जा सकते हैं। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यह व्यापक भाषा न केवल अनुबंध पी/3 को कवर करती है, बल्कि उससे कहीं अधिक को भी कवर करती है।

10. उपरोक्त दृष्टिकोण से, यह स्पष्ट है कि दिशानिर्देश, अनुबंध पी/3, अध्यादेश-1 द्वारा प्रदान की गई वैधानिक मंजूरी के भीतर पूरी तरह से शामिल हैं। कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्वीकार्य रूप से तैयार किया गया। एक बार ऐसा होने पर, इसमें थोड़ा संदेह हो सकता है कि प्रतिवादी-कॉलेज उपरोक्त दिशानिर्देशों से बंधा हुआ था। ऐसा प्रतीत होता है कि मामला परिशिष्ट-1 द्वारा किसी भी संदेह से परे रखा गया है जो विश्वविद्यालय से संबद्धता के लिए आवेदन पत्र निर्धारित करता है। उपखण्ड, (के)' निम्नलिखित में है, शर्तें:--

"एक आश्वासन कि कॉलेज को मान्यता मिलने के बाद प्रबंधन में कोई भी बदलाव होगा और शिक्षण स्टाफ में सभी बदलावों की सूचना तुरंत कुलपति को दी जाएगी कि संस्थान ईमानदारी से अधिनियम, क़ानून, अध्यादेश और विनियमों के प्रावधानों का पालन करेगा। विश्वविद्यालय, कार्यकारी परिषद या उसकी ओर से समय-समय पर जारी किए गए किसी भी निर्देश के बारे में।

इससे यह और भी स्पष्ट हो जाएगा कि संबद्ध कॉलेज न केवल विश्वविद्यालय के अधिनियम, क़ानून, अध्यादेशों और विनियमों के सभी प्रावधानों का पालन करने के लिए बाध्य हैं, बल्कि कार्यकारी परिषद या उसकी ओर से समय-समय पर जारी किए गए किसी भी निर्देश का भी पालन करने के लिए बाध्य हैं। .

11. अपने मुख्य रुख से इनकार करते हुए कि कोई वैधानिक प्रावधान नहीं था जिसके तहत दिशानिर्देश अनुलग्नक पी/3 जारी किए गए थे, श्री कुलदीप सिंह ने फिर निराशा का तर्क दिया। यह जोरदार ढंग से तर्क देने की कोशिश की गई कि अध्यादेश-1 के प्रावधान स्वयं खराब हैं और या तो अधिनियम के दायरे से बाहर हैं या अन्यथा असंवैधानिक हैं। हम पत्र के स्तर पर इस तरह के किसी भी विवाद को उठाने की न तो सराहना करने में असमर्थ हैं, न ही इसकी अनुमति देने में असमर्थ हैं। पेटेंट अपील. संपूर्ण रिट याचिका के संदर्भ से पता चलता है कि आरोप लगाना तो दूर, ऐसा कोई संकेत भी नहीं था कि अधिनियम का अध्यादेश-1 या तो मूल क़ानून के दायरे से बाहर था या असंवैधानिक था। दरअसल पूरी रिट याचिका में ब्रडिनेंस-1 का कोई विशेष संदर्भ भी नहीं है। अंततः श्री कुलदीप सिंह ने इसे निष्पक्ष रूप से स्वीकार कर लिया। संवैधानिकता या अधिनियम के दायरे से बाहर होने के कारण किसी भी अध्यादेश के खिलाफ कोई विशेष चुनौती नहीं दी गई। नतीजतन, पूरी याचिका में इस तरह की प्रस्तुति के लिए बिल्कुल भी आधार नहीं रखा गया था। हालाँकि, इससे भी अधिक यह स्वीकार किया गया तथ्य है कि विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष किसी भी स्तर पर, निहितार्थ से भी ऐसा तर्क उठाया गया प्रतीत नहीं होता है। हमारे सामने भी, उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील का मूल रुख यह था कि अनुबंध पी/3 ऑर्डिननी-1 द्वारा कवर

नहीं किया गया था, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, हम इसकी समग्रता में प्रतिकार करने के इच्छुक हैं। इसलिए, हम इस विलंबित चरण में एक बिल्कुल नया आधार तैयार करने की अनुमति देने में असमर्थ हैं जिसके लिए विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष दलीलों या तर्कों में कोई आधार मौजूद नहीं है।

12. इसलिए, पूर्वगामी अनुच्छेदों में चर्चा के आलोक में, प्रारंभ में तैयार किए गए प्रश्न का उत्तर सकारात्मक होना चाहिए। यह माना जाता है कि दिशानिर्देश, अनुबंध पी/3, वैधानिक प्रावधानों के दायरे में हैं और इसलिए वैध हैं। परिणामस्वरूप यह होगा कि दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए विश्वविद्यालय कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई करने और संबद्धता वापस लेने और इसके उल्लंघन में प्रवेश पाने वाले छात्रों को पंजीकरण से इनकार करने का हकदार है। इसलिए, हम विद्वान एकल न्यायाधीश के विपरीत दृष्टिकोण अपनाने के लिए बाध्य हैं और इसलिए, उनके फैसले को रद्द किया जाना चाहिए और प्रतिवादी-कॉलेज द्वारा दायर की गई रिट याचिका को खारिज कर दिया जाता है।

13. हालाँकि, यह स्पष्ट होगा कि अपील की अनुमति अनिवार्य रूप से बी.एड में प्रवेश पाने वाले छात्रों के लिए अनकही कठिनाई का कारण होगी। वह वर्ग जो विश्वविद्यालय और प्रतिवादी कॉलेज के बीच विवाद का दुर्भाग्यपूर्ण और निर्दोष शिकार होगा। इसलिए, हमने इसकी अनुमति की स्थिति में पार्टियों का रुख जानने के लिए अपील को फिर से सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था। श्री एस.सी. मोहंता, विद्वान अधिवक्ता। विश्वविद्यालय ने बहुत निष्पक्षता से कहा था कि यदि प्रतिवादी कॉलेज अब विश्वविद्यालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनारक्षित रूप से पालन करता है, तो विश्वविद्यालय उन लगभग सौ छात्रों को दंडित नहीं करना चाहेगा, जो बीएड में शामिल हुए थे। कक्षा और कॉलेज की असंबद्धता भी वापस लें। हमारे सामने प्रतिवादी-कॉलेज की ओर से श्री कुलदीप सिंह ने सीधे कहा कि प्रतिवादी-कॉलेज इसके बाद उक्त दिशानिर्देशों का पालन करेगा। मामले को देखते हुए निर्देश दिया जाता है कि बीएड के छात्र। कक्षा को विश्वविद्यालय द्वारा विधिवत पंजीकृत किया जाएगा और इसके अलावा प्रतिवादी-कॉलेज द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारियों को आवश्यक वचन पत्र दिए जाने पर; उसकी असंबद्धता वापस ले ली जाएगी।

14. अपील का निपटारा इन शर्तों पर किया जाता है। स्नान पक्षों के निष्पक्ष रुख को देखते हुए हम उन पर उनका खर्च खुद उठाने के लिए छोड़ देते हैं।

15. अपील की अनुमति.

एसएस संधावाला, सीजे

1. क्या कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा बी.एड में प्रवेश के प्रयोजनों के लिए संबद्ध सभी शिक्षा महाविद्यालयों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं? 1977-78 के सत्र के लिए पाठ्यक्रम (अनुलग्नक पी. 3), कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय अधिनियम, 1956 के तहत बनाए गए अध्यादेश 1 के वैधानिक प्रावधानों के दायरे में हैं, एकान्त हैं; यद्यपि सार्थक, प्रश्न जो लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के तहत इस अपील में उठता है।

2. यद्यपि उपरोक्त मुद्दा स्पष्ट रूप से कानूनी है, फिर भी इसे जन्म देने वाले तथ्यों के मैट्रिक्स में कुछ विस्तृत नोटिस की आवश्यकता है। रूरल कॉलेज सोसायटी द्वारा प्रबंधित रूरल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, कैथल, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत एक निकाय है । इसकी स्थापना वर्ष 1970 में हुई थी और इसमें कोई गंभीर विवाद नहीं है कि सोसायटी का एक उद्देश्य और उद्देश्य ग्रामीण जनता के बीच सामाजिक और राजनीतिक शिक्षा के लिए शैक्षणिक संस्थानों को बनाए रखना था। मूल रूप से, यह संस्थान पंजाब विश्वविद्यालय से संबद्ध था, जिसका उस समय इस क्षेत्र पर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र था, लेकिन जुलाई 1978 में इसे वहां से असंबद्ध कर दिया गया और कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय से संबद्ध कर दिया गया। प्रतिवादी कॉलेज और विश्वविद्यालय के बीच मुकदमेबाजी का एक इतिहास है जिसकी अब कोई प्रासंगिकता नहीं है और यह उल्लेख करना पर्याप्त है कि 1977-78 के सत्र के लिए, विश्वविद्यालय ने बी.एड में प्रवेश के लिए दिशानिर्देश आगे बढ़ाए थे। कक्षाएं (रिट याचिका के लिए अनुलग्नक पी/3) और आगे निर्देश दिया कि हरियाणा में अधिवास रखने वाले छात्र, चाहे वे ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों से संबंधित हों, प्रवेश के लिए पात्र होंगे। प्रतिवादी-कॉलेज ने दिशानिर्देश जारी करने पर आपत्ति जताते हुए आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय के पास छात्रों को प्रवेश देने के अपने अधिकार को रोकने का कोई अधिकार नहीं है और न ही उसे निर्देशों के तहत केवल हरियाणा राज्य के छात्रों तक ही प्रवेश सीमित करने के लिए मजबूर किया जा सकता है, भले ही वे शहरी या ग्रामीण हों। पृष्ठभूमि।

3. कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के बावजूद, प्रतिवादी-कॉलेज ने 24 जुलाई, 1977 के 'द ट्रिब्यून' में एक प्रवेश सूचना डाली कि केवल भारत में कहीं भी किसी गाँव में जन्मे या शिक्षित व्यक्तियों को ही कॉलेज में प्रवेश के लिए आवेदन करने की आवश्यकता है। छात्रों के प्रवेश के चरण में, विश्वविद्यालय ने डॉ. एपी शर्मा और डॉ. बीआर गुप्ता को प्रतिवादी कॉलेज की रिपोर्ट करने वाले अन्य लोगों के साथ अध्यादेश-1 के तहत गठित प्रवेश समिति का सदस्य नियुक्त किया। कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय (जिसे इसके बाद विश्वविद्यालय कहा जाएगा) का प्रतिनिधित्व करने वाले उपरोक्त दो सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया कि हरियाणा में अधिवास रखने वाले छात्रों को इस तथ्य की परवाह किए बिना कि वे ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों से हैं, उन्हें प्रवेश दिया जाना चाहिए और जब अन्य लोग इस पर सहमत नहीं हुए, तो दोनों नामांकित सदस्य विरोध के कारण समिति से हट गए और प्रवेश साक्षात्कार में भाग नहीं लिया। शेष सदस्यों ने 100 छात्रों को प्रवेश

दिया, जिन्होंने भारत में कहीं भी ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। हालांकि, विश्वविद्यालय ने यह रुख अपनाया कि यह प्रवेश जारी किए गए दिशानिर्देशों का अपमान है। इसके परिणामस्वरूप यह अंततः अवैध हो गया, लेकिन प्रतिवादी-कॉलेज के शासी निकाय के अध्यक्ष अपने रुख पर अड़े रहे और दिशानिर्देश जारी करने की विश्वविद्यालय की शक्ति पर सवाल उठाया। अंततः, अपीलकर्ता-विश्वविद्यालय ने एक कारण बताओ नोटिस जारी किया कि क्यों न उसे असंबद्ध कर दिया जाए क्योंकि उन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पेटेंट उल्लंघन करते हुए छात्रों को प्रवेश दिया था, जिस पर प्रतिवादी-कॉलेज ने यह रुख अपनाया कि विश्वविद्यालय के पास जारी करने की कोई शक्ति नहीं है। दिशानिर्देश. अंततः, विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने रिट याचिका के अपने पत्र अनुलग्नक पी/12 के माध्यम से कॉलेज को 1977-78 के सत्र से असंबद्ध करने का निर्णय लिया और आगे सूचित किया कि कॉलेज द्वारा प्रवेशित छात्र विश्वविद्यालय द्वारा पंजीकृत नहीं हैं। .

4. दिशा-निर्देशों, अनुलग्नक पी/3 को लागू करने के विश्वविद्यालय के आग्रह और कॉलेज की असंबद्धता से व्यथित होकर, वर्तमान अपील को जन्म देने वाली रिट याचिका को प्राथमिकता दी गई। विद्वान एकल न्यायाधीश, जिनके समक्ष यह मामला पहली बार आया था, ने यह विचार किया कि चूंकि कॉलेज का रखरखाव ग्रामीण क्षेत्रों से एकत्र किए गए धन से किया जा रहा था, इसलिए सोसायटी के पास प्रथम दृष्टया कॉलेज में छात्रों के प्रवेश को विनियमित करने की शक्ति थी, और इस बात से भी संतुष्ट नहीं थे कि विश्वविद्यालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं। विश्वविद्यालय अध्यादेशों को कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत ही तैयार किया गया है, यह मानते हुए कि यह रिकॉर्ड से परे है कि कानून के किन प्रावधानों के तहत दिशानिर्देश, अनुलग्नक पी/3 जारी किए गए थे, इसे अवैध करार दिया गया और इसके परिणामस्वरूप यह भी निर्धारित किया गया। विश्वविद्यालय की असंबद्धता को छोड़कर।

5. यह लेटर्स पेटेंट अपील सबसे पहले डिवीजन बेंच के सामने आई, जिन्होंने अपने संदर्भ आदेश में यह विचार किया था कि एक मान्यता प्राप्त कॉलेज में छात्र के प्रवेश को नियंत्रित करने और विनियमित करने की शक्ति रखने वाले विश्वविद्यालय के बारे में बड़ा प्रश्न एक आधिकारिक निर्णय के योग्य है। एक बड़ी बेंच और इसी तरह मामला हमारे सामने है।

6. अब तर्क वास्तव में एक बहुत ही संकीर्ण दायरे में सिमट गया है: अपीलकर्ता-विश्वविद्यालय के विद्वान वकील श्री एससी मोहंता ने तीखा तर्क दिया है और हमारा विचार सही है कि अब एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या दिशानिर्देश अनुलग्नक पी/3 विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिनियम और उसके तहत जारी अध्यादेश की वैधानिक मंजूरी है? वकील ने इस तर्क पर जोर दिया कि विवादित दिशानिर्देश पूरी तरह से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत बनाए गए अध्यादेश-1 के

दायरे में हैं। चूंकि पूरा तर्क अनिवार्य रूप से इसके प्रावधानों के प्रासंगिक हिस्से के इर्द-गिर्द घूमता है, इसलिए शुरुआत में ही अध्यादेश-1 के खंड (2) को पढ़ना आवश्यक है;

"प्रवेश समिति.

(1) xxxx (2) प्रवेश समिति, अध्यादेशों के प्रावधानों के अधीन, निर्णय लेगी:--

(i) वह तरीका जिससे विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों और विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त/संचालित कॉलेजों में प्रवेश को विनियमित किया जाएगा;

(ii) विशेष रूप से और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, समिति निर्धारित कर सकती है:--

(ए) प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की योग्यता सूची तैयार करने के सिद्धांत, और उम्मीदवारों की श्रेणियां जिनके लिए कोई सीटें आरक्षित की जानी हैं और/या जिन्हें योग्यता सूची में प्लेसमेंट के लिए कोई वेटेज की अनुमति दी जानी है;

(बी) विभागों और कॉलेजों में उपलब्ध होने वाली सीटों की संख्या;

(सी) विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए तारीखों की अनुसूची;

(डी) ऐसे अन्य मामले जिन्हें कुलपति द्वारा संदर्भित किया जा सकता है। उपरोक्त के आलोक में, मामले का मूल यह है कि क्या उपरोक्त प्रावधान दिशानिर्देशों के लिए पर्याप्त वैधानिक स्रोत हैं, अनुबंध पी/3।

7. अब अनुलग्नक पी/3 का संदर्भ यह संकेत देगा कि यह स्पष्ट रूप से है। बी.एड में प्रवेश के लिए सभी शिक्षा महाविद्यालयों को एक दिशानिर्देश का सख्ती से पालन करना होगा। अवधि। अन्य बातों के अलावा यह सीटों के आरक्षण, उम्मीदवारों की पात्रता और इसमें शामिल विशिष्ट प्रावधान है जो विवाद का कारण है, अर्थात्, बीएड में प्रवेश के लिए हरियाणा अधिवास अनिवार्य होगा। अवधि। दिशानिर्देश वेटेज, पात्रता और योग्यता सूची के लिए भी प्रदान करते हैं। शिक्षा के मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया आदि।

8. अब अनुबंध पी/3 की सामग्री और अध्यादेश-1 के प्रावधानों को देखते हुए, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि जारी किए गए दिशानिर्देश खंड (2) द्वारा चित्रित क्षेत्र के भीतर निष्पक्ष और स्पष्ट रूप से आते हैं। अध्यादेश-1. हालाँकि, यह सबसे पहले ध्यान देने योग्य है कि अध्यादेश -1, खंड (1), एक प्रवेश समिति के गठन का प्रावधान करता है और उसके

उप-खंड (ए) से (एफ) उन कर्मियों को निर्धारित करते हैं जो विभिन्न स्थानों पर इन प्रवेश समितियों का गठन करते हैं। स्तरों और विभिन्न संस्थानों में। उप-खंड (सी) (iii) शिक्षा महाविद्यालयों सहित व्यावसायिक महाविद्यालयों से संबंधित है जो विशेष रूप से और स्पष्ट रूप से इस अध्यादेश के दायरे में आते हैं।

9. अब अध्यादेश-1 का खंड (2) प्रवेश समिति को यह तय करने का अधिकार देता है कि विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त या संचालित कॉलेजों में प्रवेश किस प्रकार विनियमित किया जाएगा। यह शक्ति जिसे व्यापक रूप से शब्दबद्ध किया गया है, किसी भी विस्तार की आवश्यकता के लिए बहुत सरल है: हालाँकि, यदि कोई आवश्यकता थी, तो उसे उप-खंड (ii) (ए) (बी) (सी) और (डी) द्वारा प्रदान किया गया है। इन; शर्तों में यह प्रावधान है कि प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की मेरिट सूची तैयार करने के सिद्धांत, की संख्या। उपलब्ध सीटें, तारीखों की अनुसूची और सभी प्रकार के अवशिष्ट प्रश्न जो कुलपति द्वारा प्रवेश-समिति को भेजे जा सकते हैं, प्रदान किए जा सकते हैं। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यह व्यापक भाषा न केवल अनुबंध पी/3 को कवर करती है, बल्कि उससे कहीं अधिक को भी कवर करती है।

10. उपरोक्त दृष्टिकोण से, यह स्पष्ट है कि दिशानिर्देश, अनुबंध पी/3, अध्यादेश-1 द्वारा प्रदान की गई वैधानिक मंजूरी के भीतर पूरी तरह से शामिल हैं। कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्वीकार्य रूप से तैयार किया गया। एक बार ऐसा होने पर, इसमें थोड़ा संदेह हो सकता है कि प्रतिवादी-कॉलेज उपरोक्त दिशानिर्देशों से बंधा हुआ था। ऐसा प्रतीत होता है कि मामला परिशिष्ट-1 द्वारा किसी भी संदेह से परे रखा गया है जो विश्वविद्यालय से संबद्धता के लिए आवेदन पत्र निर्धारित करता है। उपखण्ड, (के)' निम्नलिखित में है, शर्तें:--

"एक आश्वासन कि कॉलेज को मान्यता मिलने के बाद प्रबंधन में कोई भी बदलाव होगा और शिक्षण स्टाफ में सभी बदलावों की सूचना तुरंत कुलपति को दी जाएगी कि संस्थान ईमानदारी से अधिनियम, क़ानून, अध्यादेश और विनियमों के प्रावधानों का पालन करेगा। विश्वविद्यालय, कार्यकारी परिषद या उसकी ओर से समय-समय पर जारी किए गए किसी भी निर्देश के बारे में।

इससे यह और भी स्पष्ट हो जाएगा कि संबद्ध कॉलेज न केवल विश्वविद्यालय के अधिनियम, क़ानून, अध्यादेशों और विनियमों के सभी प्रावधानों का पालन करने के लिए बाध्य हैं, बल्कि कार्यकारी परिषद या उसकी ओर से समय-समय पर जारी किए गए किसी भी निर्देश का भी पालन करने के लिए बाध्य हैं। .

11. अपने मुख्य रुख से इनकार करते हुए कि कोई वैधानिक प्रावधान नहीं था जिसके तहत दिशानिर्देश अनुलग्नक पी/3 जारी किए गए थे, श्री कुलदीप सिंह ने फिर निराशा का तर्क दिया। यह

जोरदार ढंग से तर्क देने की कोशिश की गई कि अध्यादेश-1 के प्रावधान स्वयं खराब हैं और या तो अधिनियम के दायरे से बाहर हैं या अन्यथा असंवैधानिक हैं। हम पत्र के स्तर पर इस तरह के किसी भी विवाद को उठाने की न तो सराहना करने में असमर्थ हैं, न ही इसकी अनुमति देने में असमर्थ हैं। पेटेंट अपील. संपूर्ण रिट याचिका के संदर्भ से पता चलता है कि आरोप लगाना तो दूर, ऐसा कोई संकेत भी नहीं था कि अधिनियम का अध्यादेश-1 या तो मूल क़ानून के दायरे से बाहर था या असंवैधानिक था। दरअसल पूरी रिट याचिका में ब्रडिनेंस-1 का कोई विशेष संदर्भ भी नहीं है। अंततः श्री कुलदीप सिंह ने इसे निष्पक्ष रूप से स्वीकार कर लिया। संवैधानिकता या अधिनियम के दायरे से बाहर होने के कारण किसी भी अध्यादेश के खिलाफ कोई विशेष चुनौती नहीं दी गई। नतीजतन, पूरी याचिका में इस तरह की प्रस्तुति के लिए बिल्कुल भी आधार नहीं रखा गया था। हालाँकि, इससे भी अधिक यह स्वीकार किया गया तथ्य है कि विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष किसी भी स्तर पर, निहितार्थ से भी ऐसा तर्क उठाया गया प्रतीत नहीं होता है। हमारे सामने भी, उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील का मूल रुख यह था कि अनुबंध पी/3 ऑर्डिननी-1 द्वारा कवर नहीं किया गया था, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, हम इसकी समग्रता में प्रतिकार करने के इच्छुक हैं। इसलिए, हम इस विलंबित चरण में एक बिल्कुल नया आधार तैयार करने की अनुमति देने में असमर्थ हैं जिसके लिए विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष दलीलों या तर्कों में कोई आधार मौजूद नहीं है।

12. इसलिए, पूर्वगामी अनुच्छेदों में चर्चा के आलोक में, प्रारंभ में तैयार किए गए प्रश्न का उत्तर सकारात्मक होना चाहिए। यह माना जाता है कि दिशानिर्देश, अनुबंध पी/3, वैधानिक प्रावधानों के दायरे में हैं और इसलिए वैध हैं। परिणामस्वरूप यह होगा कि दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए विश्वविद्यालय कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई करने और संबद्धता वापस लेने और इसके उल्लंघन में प्रवेश पाने वाले छात्रों को पंजीकरण से इनकार करने का हकदार है। इसलिए, हम विद्वान एकल न्यायाधीश के विपरीत दृष्टिकोण अपनाने के लिए बाध्य हैं और इसलिए, उनके फैसले को रद्द किया जाना चाहिए और प्रतिवादी-कॉलेज द्वारा दायर की गई रिट याचिका को खारिज कर दिया जाता है।

13. हालाँकि, यह स्पष्ट होगा कि अपील की अनुमति अनिवार्य रूप से बी.एड में प्रवेश पाने वाले छात्रों के लिए अनकही कठिनाई का कारण होगी। वह वर्ग जो विश्वविद्यालय और प्रतिवादी कॉलेज के बीच विवाद का दुर्भाग्यपूर्ण और निर्दोष शिकार होगा। इसलिए, हमने इसकी अनुमति की स्थिति में पार्टियों का रुख जानने के लिए अपील को फिर से सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था। श्री एस.सी. मोहंता, विद्वान अधिवक्ता। विश्वविद्यालय ने बहुत निष्पक्षता से कहा था कि यदि प्रतिवादी कॉलेज अब विश्वविद्यालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनारक्षित रूप से पालन करता है, तो विश्वविद्यालय उन लगभग सौ छात्रों को दंडित नहीं करना चाहेगा, जो बीएड में

शामिल हुए थे। कक्षा और कॉलेज की असंबद्धता भी वापस लें। हमारे सामने प्रतिवादी-कॉलेज की ओर से श्री कुलदीप सिंह ने सीधे कहा कि प्रतिवादी-कॉलेज इसके बाद उक्त दिशानिर्देशों का पालन करेगा। मामले को देखते हुए निर्देश दिया जाता है कि बीएड के छात्र। कक्षा को विश्वविद्यालय द्वारा विधिवत पंजीकृत किया जाएगा और इसके अलावा प्रतिवादी-कॉलेज द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारियों को आवश्यक वचन पत्र दिए जाने पर; उसकी असंबद्धता वापस ले ली जाएगी।

14. अपील का निपटारा इन शर्तों पर किया जाता है। स्नान पक्षों के निष्पक्ष रुख को देखते हुए हम उन पर उनका खर्च खुद उठाने के लिए छोड़ देते हैं।

15. अपील की अनुमति.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

चाहत

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

अंबाला, हरियाणा